www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 282 | जौनपुर बुधवार, 03 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

14 नए राफेल विमानों की खरीद प्रक्रिया तेज, 94 भारत में ही बनेंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने फ्रांस को 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अनुरोध।–पत्र (स्मजजमत व ित्मुनमेज) जारी कर दिया है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये के इस संभावित रक्षा सौदे को भारत के सबसे बड़े सैन्य विमान सौदों में से एक माना जा रहा है। इस प्रस्ताव के साथ भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग का दायरा और व्यापक होने की उम्मीद है।इस प्रस्ताव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 114 विमानों में से 94 राफेल जेट भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी दासौ एविएशन किसी भारतीय साझेदार कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन करेगी। यदि यह योजना अंतिम रूप लेती है तो यह पहला अवसर होगा जब राफेल विमान का निर्माण फ्रांस के बाहर किसी अन्य देश में किया जाएगा। इस पहल को 'मेक इन इंडिया' और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे भारत में रक्षा विनिर्माण, तकनीकी विशेषज्ञता और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मंत्रालय की खरीद शाखा ने हाल ही में फ्रांस सरकार को औपचारिक अनुरोध–पत्र भेजा है। अब फ्रांस की ओर से इस प्रस्ताव पर विस्तृत जवाब आने की प्रतीक्षा है।

नीट यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की कार्रवाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नीट–यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही मामले की गहन जांच जारी है। समाचार पत्र सदस्यता सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने एक निजी कंपनी कोएम्प्ट को विवादास्पद परिचालन अनुबंध दिए जाने के संबंध में औपचारिक रूप से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ता कंपनी की तकनीकी योग्यता और पिछले प्रदर्शन के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उसे कैसे सौंपी गई।मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार कथित डेटा उल्लंघन और पेपर लीक की घटना को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि लापरवाही या मिलीभगत के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या बाहरी प्रतिनिधि। के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार कथित सुरक्षा खामियों की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए साइबर सुरक्षा एजेंसियों और परीक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर रही है।

दृढ़ निश्चय और आत्म-संयम से कठिन राह भी आसान बनती है- पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर दृढ़ निश्चय और आत्म–संयम को लेकर संस्कृत सुभाषित शेयर किया। प्रधानमंत्री ने श्एक्सश पोस्ट में लिखा, ष्दृढ़ निश्चय और आत्म–संयम वह शक्ति है, जो कठिन से कठिन राह को भी आसान बना देती है। आज हमारे युवा साथी इसी संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण में निरंतर जुटे हुए हैं।ष पीएम मोदी ने एक संस्कृत श्लोक शनिश्चित्य यः प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः। अबन्ध्यकालो वश्यात्मा स वै पण्डित उच्यतेष्ठ सोशल मीडिया पर साझा किया। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, ष्जो व्यक्ति किसी कार्य को भली–भांति सोच–समझकर दृढ़ निश्चय के साथ आरंभ करता है और उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ता, जो समय का सदुपयोग करता है तथा अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में बुद्धिमान होता है।ष बता दें कि पीएम मोदी ने सोमवार, 1 जून को कंपाउंड वर्ब (संयुक्त क्रिया) को लेकर सोशल मीडिया पर सुभाषित शेयर किया था। पीएम ने लिखा था कि कंपाउंड वर्ब (संयुक्त क्रिया) का अर्थ है– एक शब्द की विशेषता को उससे जुड़े दूसरे शब्द में स्थानांतरित कर देना या जोड़ देना। जिस व्यक्ति में ये दोनों गुण हों, उसे ही शिक्षक के कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक संस्कृत लोक शिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था सङ्क्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव।। साझा किया था। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि कुछ लोग स्वयं किसी कार्य को करने में बहुत निपुण होते हैं, ।

स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिल्ली–जर्मनी सहयोग बढ़ेगा : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के मंत्री–प्रमुख मारियो वोग्ट और उनके उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान शहरी विकास, प्रौद्योगिकी, सुशासन और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने स्मार्ट शहरों के विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्रशासन और नवाचार आधारित सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इन चर्चाओं में परिवहन व्यवस्था, जल प्रबंधन, पर्यावरण से जुड़ी तकनीकों, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी बात हुई। इन पहलों का उद्देश्य भारत और जर्मनी के बीच प्रतिभाशाली लोगों के आदान–प्रदान को और मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और जर्मनी के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, सतत विकास और मानव संसाधन विकास से जुड़ी विभिन्न पहलों के माध्यम से दिल्ली इस बढ़ती साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के मंत्री–प्रमुख मारियो वोग्ट और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में स्मार्ट शहरी विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, डिजिटल प्रशासन, नवाचार, कौशल विकास, प्रतिभाओं के आदान–प्रदान, परिवहन व्यवस्था, जल प्रबंधन, पर्यावरण तकनीकों तथा शिक्षा और कार्यबल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रपति मुर्मु, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

तेलंगाना, (एजेंसी)। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। "तेलंगाना के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहनती लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। पिछले कुछ वर्षों में, इस राज्य ने नवाचार और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मैं तेलंगाना के लोगों के निरंतर विकास और खुशहाली की कामना करती हूं।" "समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न, तेलंगाना ने अपने लोगों की रचनात्मकता, नवाचार, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कामना है कि यह अवसर सभी को राज्य के कल्याण और 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करे।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के लोगों की रचनात्मकता और उद्यमशीलता की सराहना करते हुए लिखा, "तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर तेलंगाना के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना के लोग अपनी रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए जाने जाते हैं। इस राज्य का इतिहास समृद्ध और संस्कृति गौरवशाली है, जो साहस, दृढ़ संकल्प और जुझारू भावना के प्रतीक हैं।" पीएम मोदी ने आगे कहा, "केंद्र सरकार तेलंगाना की विकास यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य 'विकसित भारत' के हमारे साझा स्वप्न को साकार करना है।

फाजिलनगर का नाम बदलने का भी ऐलान : मुख्यमंत्री योगी

कुशीनगर, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फाजिलनगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि नई पहचान भगवान महावीर से जुड़े इतिहास को सम्मान देगी। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए राज्य में कानून–व्यवस्था, विकास और जनकल्याण योजनाओं को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कुशीनगर के फाजिलनगर का नाम बदलने का प्रस्ताव हम

लोगों ने रख दिया है। अब इसे फाजिलनगर नहीं, बल्कि पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा। भगवान महावीर से इस क्षेत्र की पहचान होगी, फिर इसे फाजिल क्यों कहें? अपनी विरासत पर गौरव करना हर व्यक्ति का दायित्व है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले हर जगह सिर्फ शोषण होता था, माफियाओं को संरक्षण मिला हुआ था। बीमारियां फैल रही थीं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। हर पर्व और त्योहार पर हिंसा होती थी। आज डबल इंजन सरकार का असर है कि सिर्फ कुशीनगर में 90 हजार लोगों को आवास मिला है और लाखों लोगों के घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। इलाज, शौचालय, राशन जैसी सुविधाएं सरकार मुफ्त में दे रही है। उन्होंने कहा कि इंसेफेलाइटिस की बीमारी उसी तरह खत्म हो गई है, जैसे उत्तर प्रदेश से माफिया खत्म हो गए हैं। हमने माफिया और मच्छरों को खत्म कर दिया है। मच्छर बीमारी फैलाते थे और माफिया लोगों में बेरोजगारी बढ़ाते थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर आप अच्छे विधायक और सांसद चुनते हैं, तो वे अच्छे काम करते हैं। विकास, रोजगार, सुरक्षा, बीमारी पर नियंत्रण तथा माफिया और गुंडों पर लगाम लगाने का काम करते हैं। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने और उनकी उपज का अच्छा दाम दिलाने का भी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 498 वर्ष पूर्व अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर एक विदेशी आक्रांता ने उस पवित्र स्थल को ध्वस्त कर दिया था ।

गांधी भवन डीयू के निदेशक प्रो.केपी सिंह जी की दो पुस्तकों का लोकार्पण समारोह किया गया

उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है,वह किसी भी राज्य से पीछे नहीं है–श्री गुरमीत सिंह,राज्यपाल उत्तराखंड

दिल्ली ब्यूरो चीफ पी अस्थाना

नई दिल्ली। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष,गांधी भवन के निदेशक,प्रो.केपी सिंह द्वारा लिखित उत्तराखंड के राज्यपाल ले. जनरल श्री गुरमीत सिंह के जीवन पर केंद्रित दो पुस्तकों का लोकार्पण उत्तराखंड निवास चाणक्य पुरी के सभागार में संपन्न हुआ ।प्रो.केपी सिंह द्वारा संपादित एवं अटल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक , A The Leadership Funnel. Lt- Gn- Gurmit Singh's journey as Governer और From Thought to Ink . A Collection of Lt-Gn Gurmit Singh's writings का विमोचन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी के कर कमलों से हुआ। इस आयोजन में राष्ट्रीय सैनिक संघ के सैनिक, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य और प्रोफेसर शामिल हुए ।महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह का स्वागत प्रो केपी सिंह ने अंग वस्त्र,पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर किया ।अटल प्रकाशन से उपासना काबरा ने अपने स्वागत वक्तव्य में महामहिम राज्यपाल महोदय एवं सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने अटल प्रकाशन द्वारा आधुनिक तकनीकी पर आधारित पुस्तकों के प्रकाशन के विषय में जानकारी दी ।उन्होंने प्रो केपी सिंह द्वारा संपादित इन दो महत्वपूर्ण पुस्तकों के विमोचन के लिए आभार प्रकट किया। दोनों पुस्तकों का परिचय देते हुए प्रोफेसर केपी सिंह ने बताया कि प्रथम पुस्तक ,The Leadership Funnel में माननीय राज्यपाल महोदय के उत्तराखंड के बहुआयामी विकास में योगदान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। पहाड़ों की यथास्थिति को बनाए रखते हुए उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करना ।उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में विकास के साथ–साथ पर्यटन एवं विशेष रूप से देवभूमि के मूल स्वभाव को जीवंत रखते हुए तीर्थ स्थलों के विकास में अभूतपूर्व योगदान को रेखांकित किया गया ।द्वितीय पुस्तक From Thought to Ink के विषय में बात करते हुए कहा कि इस पुस्तक में लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी ने स्वयं के लेखन चिंतन मनन आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी ने अपने संबोधन में कहा कि यह पुस्तकें केवल प्रकाशन नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की विकास यात्रा,जनसेवा के संकल्प और राष्ट्रहित के दृष्टिकोण का जीवंत दस्तावेज हैं ।उन्होंने कहा कि 'द लीडरशिप फनल' उनके व्यक्तिगत कार्यकाल की नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड के युवाओं, महिलाओं,सैनिकों, शिक्षकों,वैज्ञानिकों और कर्मयोगियों की सामूहिक यात्रा को प्रतिबिंबित करती है ।उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में चार दशकों से अधिक सेवा और राज्यपाल के रूप में दायित्व निर्वहन के दौरान राष्ट्र प्रथम उनके जीवन का मूल आधार रहा है ।राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का मार्ग विकसित राज्यों से होकर गुजरता है और उत्तराखण्ड को शिक्षा,अनुसंधान, नवाचार,पर्यटन,संस्कृति एवं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है वह किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह ने आगे कहा कि 'थॉट टू इंक' केवल विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण,शिक्षा,युवा सशक्तिकरण,सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद का प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारे मन में उठने वाले विचारों (थॉट) को जब हम स्याही (ink) से उसे शब्दों में उतारते हैं तो वह स्वयं के लेखन से नहीं जुड़ते बल्कि सबके लिए होते हैं और वही कार्य प्रो केपी सिंह ने अपने लेखन के माध्यम से पुस्तकाकार रूप देकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुस्तकें युवाओं, शोधार्थियों,प्रशासकों और समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित करेंगी। श्री गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रो केपी सिंह का मेरे प्रति एक विशेष लगाव है इसी कारण उन्होंने पहली पुस्तक में उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में मेरे कार्यकाल एवं दूसरी पुस्तक में मेरे चिंतन और मनन से निकले विचारों को संकलित करने का अद्वितीय प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि लिखित विचार कभी नहीं मरते,वे पुस्तकों में जीवित रहते हैं। पुस्तकें पुस्तकालयों में सुरक्षित रहती है,मनुष्य भले ही संसार को छोड़ दे लेकिन उसके विचार भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे ।प्रो. सिंह ने मन में उठने वाले विचारों को संग्रहित करके देश हित में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। जिसे सदैव याद किया जाएगा ।समस्त विकसित नदियों की स्वच्छता,ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती,नारी सशक्तिकरण, आधुनिक तकनीकी,शोध को बढ़ावा देना,भारतीय ज्ञान परंपरा को और पोषित करना यह मेरा संकल्प है। राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह ने जिवनहीज जव पदा पुस्तक के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि इस पुस्तक में उन विषयों पर संवाद करने का प्रयास किया गया है जो राष्ट्र निर्माण से जुड़े हैं ।पुस्तक में मेरे पदों की यात्रा का नहीं अपितु सेवा की यात्रा का चित्रण है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी देश के प्रति अमूल्य योगदान रहा है ।उन्होंने कहा कि हम सभी को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मोदी जी का सहयोग करना चाहिए ।उन्होंने प्रो.के.पी.सिंह के विषय में बात करते हुए कहा कि ऐसी अद्वितीय पुस्तकों का लेखन प्रो. केपी सिंह जैसे अद्वितीय प्रतिभा के धनी लेखक ही कर सकते हैं। यह पुस्तकें और इनके भीतर उपस्थित वाक्य एवं चित्र लंबे समय तक सभी को अपने आस पास सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा देती रहेंगी। साथ ही उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान विभाग में नवाचार के प्रयोगों,आधुनिक तकनीकी प्रयोगों से पुस्तकालयों को अत्याधुनिक रूप देने के प्रो. के.पी.सिंह के योगदान को ऐतिहासिक बताया ।प्रकाशक श्री संदीप जैन एवं अटल प्रकाशन की टीम को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देते हुए उनके शोध, समर्पण और परिश्रम की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में प्रो.राकेश कुमार भट्ट ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया ।कार्यक्रम का संचालन डॉ. पिंकी शर्मा ने किया ।कार्यक्रम में अटल प्रकाशन के निदेशक डॉ.संदीप जैन, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों में,खालसा कॉलेज के प्राचार्य प्रो.गुरमोहिंदर सिंह,प्रो.हंसराज सुमन,प्रो.मनोज कुमार कैन,डॉ ज्ञानेंद्र नारायण सिंह,राष्ट्रीय सैनिक संस्था के सैनिक कर्नल मुकेश त्यागी,गौरव सेनानी चंदन सिंह,गौरव सेनानी गणेश दत्त,लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश शर्मा, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी,मोनिका गोयल,डॉ मधु सिंह ,एडवोकेट अंशु त्यागी एवं संध्या त्यागी आदि गणमान्य उपस्थित

भाजपा सरकार देश के लोगों पर हर तरफ से महंगाई थोप रही है –कमलनाथ

भोपाल, (एजेंसी)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सोमवार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी की आलोचना की। उन्होंने उपभोक्ताओं एवं छोटे व्यवसायों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से करों में कटौती की मांग की। मध्य प्रदेश भर में कर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में रविवार से फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कीमतों में 44 रुपए तक की वृद्धि हुई है। भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,116.50 रुपए तक पहुंच गई है ।इंदौर में यह कीमत 3,222.50 रुपए, जबलपुर में 3,290 रुपए, ग्वालियर में 3,338.50 रुपए और उज्जैन में 3,250 रुपए है। बाजार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन महीनों में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में लगभग 1,300 रुपए की वृद्धि हुई है। इससे पहले 1 मई को भी कीमतों में संशोधन किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की कीमतों में बार–बार बढ़ोतरी करके महंगाई बढ़ा रही है ।पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा शादी के मौसम के दौरान बढ़ती एलपीजी कीमतों के प्रभाव पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जुलाई तक मध्य प्रदेश में 20,000 से अधिक शादियों की उम्मीद के साथ, होटलों, खानपान कंपनियों और खाद्य विक्रेताओं को परिचालन लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कई व्यवसायों ने पहले ही एडवांस बुकिंग स्वीकार कर ली थी ।

संपादकीय

दो चुनौतियां, एक सबक

सफल औद्योगिक राष्ट्र वे रहे हैं, जिन्होंने जिस उत्पाद पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी पूरी आपूर्ति शृंखला अपने यहां स्थापित की। सफलता का एक सूत्र यह भी है कि उत्पादित वस्तुओं का एक बड़ा घरेलू बाजार भी हो। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर उद्योग इस समय श्मेमफ्लेशन्य की चुनौती का सामना कर रहा है। इस शब्द का अर्थ है मेमरी चिप्स की कमी के कारण बढ़ी महंगाई। मेमरी चिप्स की कीमत आसमान पर है, जिससे सेमीकंडक्टर महंगे हो गए हैं। इनका भारी असर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों– खासकर मोबाइल फोन के उत्पादन पर पड़ा है। भारत के लिए ये घटनाक्रम इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि मेक इन इंडिया और चाइना1 रणनीति की कोई सफलता अपने देश में है, तो वह मोबाइल फोन की मैनुफैक्चरिंग (अथवा असेंबलिंग) है। हालिया वर्षों में भारत से मोबाइल फोन का निर्यात तेजी से बढ़ा है। मगर साथ ही मोबाइल फोन के पाट–पुर्जों का आयात भी बढ़ा है, जो ज्यादातर चीन, दक्षिण कोरिया या ताइवान जैसे देशों से होता है। जो चीजें बाहर से आती हैं, उनमें मेमरी चिप्स भी हैं। नतीजतन, ताजा ट्रेंड से भारत स्थित कारखानों की मुश्किलें बढ़ी हैं। एक अन्य खबर है कि अमेरिका में आयात शुल्क संबंधी जारी अनिश्चय के कारण भारत से सोलर मॉड्यूल का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वर्ष की पहली तिमाही में सिर्फ एक को छोड़कर अमेरिका के लिए बाकी सभी भारतीय कंपनियों का निर्यात शून्य रहा। सोलर पैनल्स पर ट्रंप प्रशासन ने 230 फीसदी टैरिफ लगा रखा है, जबकि भारतीय सौर उद्योग का अमेरिका प्रमुख बाजार है। तो सार यह कि जहां मोबाइल फोन उद्योग आयात निर्भरता के कारण पैदा हुई चुनौती झेल रहा है, वहीं सौर ऊर्जा उद्योग निर्यात निर्भरता संबंधी। तो सबक क्या है? सफल औद्योगिक राष्ट्र वे रहे हैं, जिन्होंने जिस उत्पाद पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी पूरी आपूर्ति शृंखला अपने यहां स्थापित की। इसीलिए इंडस्ट्रीयल पार्कों को इतनी अहमियत दी जाती है। साथ ही सफलता का एक सूत्र यह भी है कि उत्पादित वस्तुओं का एक बड़ा घरेलू बाजार हो, जो भू–राजनीतिक एवं व्यापार जनित संकटों के समय संबंधित उद्योग का सहारा बना रहे। भारत में उद्यम के जो सफल क्षेत्र हैं, अब साफ है कि उनमें इन पहलुओं की उपेक्षा की गई। उन्हें अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की सोच से इतर स्थापित किया गया। अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।

वीआईपी अपराधियों के लिए जेल मानो होटल

रजनीश कपूर

सवाल है कि पैरोल का सिलसिला कानून है या विशेषाधिकार? हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट के तहत कैदियों को पैरोल और फरलो का प्रावधान है। इस कानून के अनुसार, एक साल की सजा पूरी करने के बाद कोई भी कैदी प्रति वर्ष 10 सप्ताह की पैरोल और 21 दिन की फरलो का हकदार है। राम रहीम को 2020 से 2026 तक 16 बार से ज्यादा पैरोलध्फरलो मिल चुकी है। कुल मिलाकर 430 से अधिक दिन वे जेल से बाहर रहे। भारत में कानून की समानता का सिद्धांत संविधान का मूल आधार है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सब समान हैं। लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके उलट दिखती है। बलात्कार और हत्या के मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह का मामला इसका स्पष्ट उदाहरण है। रोहतक की सुनारिया जेल, जहां वे बंद हैं, उनके लिए लगभग होटल जैसी सुविधाओं का केंद्र बन गई है, जबकि आम कैदी कठिन परिस्थितियों में सजा काटते हैं। उल्लेखनीय है कि 2017 में दो साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 वर्ष की सजा पाने के बाद राम रहीम रोहतक जेल में बंद हैं। बाद में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रंजीत सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास भी मिला। जेल में उनके लिए विशेष सेल, बोतलबंद पानी, सहायक कर्मी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। एक पूर्व कैदी ने आरोप लगाया था कि राम रहीम को अन्य कैदियों से ज्यादा समय मुलाकात के लिए मिलता है। जबकि सामान्य कैदियों को मात्र 20 मिनट मिलते हैं, वहीं राम रहीम को घंटों की छूट दी जाती रही। जेल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन राम रहीम को बार–बार मिलने वाली पैरोल और फरलो ने संदेह बढ़ाया है। रोहतक जेल में उनका रहना आम कैदियों के लिए कठिनाइयों के बीच विपरीत तस्वीर पेश करता है। जहां सामान्य कैदी भीड़भाड़, सीमित संसाधनों और सख्त नियमों में रहते हैं, वहीं राम रहीम को लगातार रिहाई और आरामदायक व्यवस्था मिलती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि पैरोल का सिलसिला कानून है या विशेषाधिकार? हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट के तहत कैदियों को पैरोल और फरलो का प्रावधान है। इस कानून के अनुसार, एक साल की सजा पूरी करने के बाद कोई भी कैदी प्रति वर्ष 10 सप्ताह की पैरोल और 21 दिन की फरलो का हकदार है। फरलो को कैदी का अधिकार माना जाता है, जो सामाजिक और पारिवारिक संबंध बनाए रखने के लिए दी जाती है, जबकि पैरोल के लिए विशिष्ट कारणों की आवश्यकता होती है। लेकिन राम रहीम के मामले में इसका दुरुपयोग स्पष्ट दिखता है। 2020 से 2026 तक उन्हें 16 बार से ज्यादा पैरोलध्फरलो मिल चुकी है। कुल मिलाकर 430 से अधिक दिन वे जेल से बाहर रहे। मई 2026 में मिली 30 दिन की पैरोल पर वे जेल से बाहर निकले और सिरसा डेरे पहुंचे। यह उनकी 2026 की दूसरी पैरोल थी। कथित तौर पर ये रिहाइयां अक्सर बिना किसी ठोस कारण के दी गई हैं। क्योंकि ये रिहाइयां अक्सर चुनावों, धार्मिक कार्यक्रमों या त्योहारों के आसपास दी गईं। 2022 पंजाब, 2023 राजस्थान, 2024 हरियाणा चुनावों से पहले भी ऐसी छूट मिली। डेरे के लाखों अनुयायी एक बड़ा वोट बैंक हैं, जिसका राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप लगते रहे। बलात्कार और हत्या के अपराधी राम रहीम की बार–बार रिहाई पीड़ित परिवारों के लिए अपमानजनक है। 2017 में सजा के बाद हुए दंगे में 40 लोगों की मौत हुई थी। गवाहों पर दबाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति समेत कई संगठन इन पैरोलों की निंदा करते हैं। पत्रकार अंशुल छत्रपति ने इसे ष्कानून का मजाकष बताया। आम कैदियों के लिए पैरोल मिलना मुश्किल होता है। हरियाणा के आंकड़ों के अनुसार, जेलों में हजारों कैदी हैं, लेकिन सीमित संख्या को ही ऐसी छूट मिलती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राम रहीम को मिलने वाली लगातार रिहाइयां अन्य कैदियों में असंतोष पैदा करती हैं। गौरतलब है कि रोहतक की सुनारिया जेल सामान्य रूप से क्षमता से अधिक भरी रहती है। कैदियों को बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन राम रहीम के लिए यहां विशेष इंतजाम किए जाते रहे। आरामदायक रहन–सहन, बेहतर भोजन और लगातार बाहर जाने की छूट। यह जेल उनके लिए सजा की जगह आरामगाह बन गई है। एक तरफ तो जेल सुधार की बातें होती रहती हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उच्च प्रभाव वाले कैदियों को मिलने वाली सुविधाएं व्यवस्था की कमजोरी उजागर करती हैं। जहां गरीब या सामान्य अपराधी सालों जेल में सड़ते हैं, वहीं प्रभावशाली व्यक्ति यहाँ एक लक्जरी होटल जैसी जिंदगी जीते दिखते हैं।

परीक्षाओं में गड़बड़ियां मोदी सरकार के आर्थिक प्रगति के दावों पर एक दुखद टिप्पणी

के. रवींद्रन

राजनीति समाचार परीक्षाओं से जुड़े ये घोटाले शासन की राजनीतिक संस्कृति में एक परेशान करने वाला रूझान भी उजागर करते हैं। संस्थाएं अक्सर तभी प्रतिक्रिया देती हैं, जब जनता का आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। स्वीकारोक्ति से पहले इनकार किया जाता है। संकट के बाद ही समितियां गठित की जाती हैं। सुधार के वादे तब किए जाते हैं। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का वादा, मोदी सरकार के राजनीतिक संदेशों का एक सबसे लगातार दोहराया जाने वाला विषय बन गया है। इसे राष्ट्रीय पुनरुत्थान के सुबूत के तौर पर पेश किया जाता है।एक चुनावी नारे के तौर पर इसमें जाहिर तौर पर आकर्षण है। लेकिन राष्ट्रीय प्रगति की असली कसौटी, अर्थव्यवस्था का कुल आकार नहीं है। असली कसौटी यह है कि क्या सरकार निष्पक्ष रूप से काम करती है, क्या सार्वजनिक संस्थानों पर लोगों का भरोसा है, और क्या नियमों की गैर–मौजूदगी में सजा पाने के बजाय युवा नियमों द्वारा सुरक्षित महसूस करते हैं? यही कारण है कि परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद, प्रशासनिक विफलता से कहीं ज्यादा गहरी चीज पर चोट करते हैं। वे राष्ट्रीय उपलब्धि की बयानबाजी और उन लाखों परिवारों के वास्तविक जीवन के अनुभव के बीच के अंतर को उजागर करते हैं, जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं। जिस देश में शिक्षा सामाजिक गतिशीलता की मुख्य सीढ़ी बनी हुई है, वहां परीक्षा महज एक जांच नहीं है। यह अक्सर वर्षों के त्याग की परिणति होती है। माता–पिता अपनी संपत्ति बेच देते हैं, छात्र अत्यधिक मानसिक तनाव झेलते हैं, परिवार शहर बदल लेते हैं, कोचिंग सेंटर घर की जमा–पूंजी खा जाते हैं, और किशोरों पर ऐसी उम्मीदों का बोझ डाल दिया जाता है, जो कई वयस्कों को भी दबा दें। जब ऐसी परीक्षाओं की पवित्रता पर आंच आती है, तो इसका नुकसान सिर्फ मार्कशीट या दाखिले तक ही सीमित नहीं रहता। यह नागरिक और सरकार के बीच हुए नैतिक समझौते पर एक हमला होता है।नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) इस टूटन का प्रतीक बन गई है। इसका उद्देश्य उच्च–दांव वाली परीक्षाओं में मानकीकरण, दक्षता और विश्वसनीयता लाना था। इसके बजाय, इसे बार–बार विवादों के केंद्र में धकेल दिया गया है। इसे न्यायिक जांच, जनता के गुस्से और छात्रों के बीच भरोसे में भारी कमी का सामना करना पड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियों ने उसी बात को जाहिर किया है, जो कई परिवार पहले से ही महसूस कर रहे थे कि जिस संस्था पर युवा नागरिकों के भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह लापरवाही, अपारदर्शिता या बचाव की मुद्रा वाले नौकरशाही रवैये के साथ काम नहीं कर सकती। जब उम्मीदवार और माता–पिता निराशा में डूब जाते हैं, जब अनिश्चितता हफ्तों तक खिंचती रहती है, जब पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों का जवाब पहले इनकार से दिया जाता है और बाद में डैमेज कंट्रोल (नुकसान की भरपाई) से, तो विश्वसनीयता को हुए नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो जाता है।बड़ा मुद्दा यह नहीं है कि क्या टेक्नालॉजी लाई जा सकती है, क्या परीक्षाओं को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जा सकता है, या क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल को और ज्यादा विस्तृत बनाया जा सकता है? ये जरूरी सुधार हो सकते हैं, लेकिन ये ईमानदारी का विकल्प नहीं हैं। एक भ्रष्ट कागजी प्रक्रिया की जगह एक भ्रष्ट डिजिटल प्रक्रिया ले सकती है। एक दोषपूर्ण मानवीय श्रृंखला की जगह एक दोषपूर्ण तकनीकी श्रृंखला ले सकती है। अगर सिस्टम को डिजाइन करने वाले, ठेका देने वाले, निगरानी करने वाले और ऑडिट करने वाले लोग जवाबदेह नहीं हैं, तो टेक्नालॉजी एक और ऐसी परत बन जाती है जिसके पीछे जिम्मेदारी छिप सकती है। भारत की शासन–प्रशासन से जुड़ी विफलताएं अक्सर नियमों के न होने की वजह से नहीं, बल्कि नियमों को चुनिंदा तरीके से तोड़ने–मरोड़ने, सुरक्षा उपायों को कमजोर करने, और सार्वजनिक संस्थानों को जनता के भरोसे का संरक्षक मानने के बजाय अपनी सुविधा का जरिया समझने की प्रवृत्ति से पैदा होती हैं।सीबीएसई विवाद इसी चिंता को और मजबूत करता है। पहली नजर में जो चीज परीक्षा के संचालन या मूल्यांकन में एक तकनीकी विफलता लगती है, उसे महज एक दुर्घटना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, अगर +फैसलों की श्रृंखला कुछ ज्यादा ही सोची–समझी साजिश की ओर इशारा करती हो। जब कोई ठेका ऐसी कंपनी को मिलता है जिसे पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका हो, और जब आरोप लगते हैं कि नियमों में इस तरह से बदलाव किए गए जिससे ऐसा नतीजा मुमकिन हो पाया, तो यह मामला महज अकुशलता का एक साधारण मामला नहीं रह जाता। यह संस्थागत धोखे का सवाल बन जाता है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक खरीद एक ऐसी प्रक्रिया बनकर रह गई है, जहां पात्रता की शर्तों को ढीला किया जा सकता है, सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज किया जा सकता है, और नुकसान हो जाने के बाद जवाबदेही को खत्म किया जा सकता है? यह बात इसलिए मायने रखती है, क्योंकि परीक्षाएं उन कुछ जगहों में से एक हैं जहां आम नागरिकों को अब भी यह उम्मीद होती है कि पैसा, रसूख और पहुंच के ऊपर योग्यता की ही जीत होगी। इस स्तर पर शासन की गुणवत्ता के आधार पर ही इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सरकार के समर्थक यह तर्क दे सकते हैं कि भारत के विशाल आकार के कारण ऐसी असफलताओं से बचना मुश्किल है। भारत की परीक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे जटिल प्रणालियों में से एक है। लेकिन विशाल आकार को लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। बल्कि, विशाल आकार तो और भी अधिक कड़े सुरक्षा उपायों की मांग करता है, न कि कमजोर उपायों की। एक ऐसा देश जो उन्नत डिजिटल भुगतान प्रणालियां बना सकता है, बड़े पैमाने पर कल्याणकारी डेटाबेस लागू कर सकता है, और देशव्यापी राजनीतिक अभियानों का प्रबंधन कर सकता है, वह तब अपनी बेबसी का रोना नहीं रो सकता, जब छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो। प्रशासनिक जटिलता केवल चुनौती को स्पष्ट करती हैय यह असफलता का औचित्य सिद्ध नहीं करती।परीक्षाओं से जुड़े ये घोटाले शासन की राजनीतिक संस्कृति में एक परेशान करने वाला रूझान भी उजागर करते हैं। संस्थाएं अक्सर तभी प्रतिक्रिया देती हैं, जब जनता का आक्रोश इतना बढ़ जाता है कि उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। स्वीकारोक्ति से पहले इनकार किया जाता है। संकट के बाद ही समितियां गठित की जाती हैं। सुधार के वादे तब किए जाते हैं, जब परिवार पहले ही चिंता और अपमान झेल चुके होते हैं।

विधानसभा चुनावों के हाल के चक्र के बाद जरूरत और भी बढ़ गयी

राजेंद्र

विपक्ष के मैदान में बने होने और एकजुट होने के संदेश की, विधानसभा चुनावों के हाल के चक्र के बाद जरूरत और भी बढ़ गयी है। हालांकि, इस चक्र में जिन पांच विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उनमें से केरल में भाजपा अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, मुख्य मुकाबले से बाहर ही रही है और इस तरह, इंडिया ब्लाक से संबद्घ दो मोर्चों के बीच ही सत्ता का बदलाव हुआ है। विपक्षी इंडिया ब्लाक की 6 जून को प्रस्तावित बैठक पर, विपक्ष के हमदर्दों की ही नहीं, सत्ता पक्ष के हमदर्दों की भी नजरें रहेंगी और खुद को तटस्थ मानने वालों की भी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मुश्किल से महीने भर बाद इस बैठक का बुलाया जाना, बेशक अपने आप में एक संदेश है। यह संदेश, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, यही हो सकता है कि विपक्ष न हारा है और न मैदान से भागा है। विपक्ष अब भी मैदान में बना हुआ और एकजुट है।बेशक, विपक्ष की एकजुटता के पहलू से इस बैठक को लेकर कुछेक सवाल भी हैं, जिनके उत्तर इस बैठक में पूरी तरह से मिल ही जाएंगे यह कहना मुश्किल है। एक ओर जहां यह पूरी तरह से स्पष्टङ्ख है कि प. बंगाल में सत्ता खोने के बाद, नयी–नयी सत्ता पर काबिज हुई भाजपा की हिंसा से लेकर, व्यवस्थित सांगठनिक तोड़–फोड़ तथा निचले स्तर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के दलबदल के संकटों का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस, इस बैठक में बढ़–चढ़कर हिस्सा ही नहीं लेगी, वास्तव में चुनावों के बाद जल्दी ही इस बैठक के बुलाए जाने के पीछे उसके आग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी ओर, अब तक इंडिया ब्लाक में महत्वपूर्ण तथा भरोसेमंद घटक की भूमिका अदा करती आयी, डीएमके क्या रुख अपनाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।याद रहे कि तमिलनाडु में इस विधानसभा चुनाव में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने, एक सिने सितारे, विजय की पार्टी, टीवीके के हाथों उसी तरह सत्ता ही नहीं गंवायी, जैसे बंगाल में टीएमसी ने गंवायी है, चुनाव बाद के घटनाक्रम में यह गठबंधन भी बिखरता नजर आया। हालांकि, राज्य की जनता का फैसला टीवीके के पक्ष में ही था इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी टीवीके पूर्ण बहुमत से करीब दस सीटें पीछे रह गयी थी। इस पृष्ठङ्खभूमि में कांग्रेस ने फौरन डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन से नाता तोड़कर, टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने और उसकी सरकार में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस पर डीएमके की काफी नाराजगी देखने को मिली। यहां तक कि उसकी ओर से लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर, डीएमके सांसदों के लिए इंडिया ब्लाक से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग भी कर दी गयी। इस पृष्ठङ्खभूमि में डीएमके इंडिया गठबंधन से दूरी बनाती है या फौरी नाराजगी के बाद धीरे–धीरे वापसी करती है, इस पर राजनीतिक प्रेक्षकों की खास नजर रहेगी।कहने की जरूरत नहीं है कि विपक्ष के मैदान में बने होने और एकजुट होने के संदेश की, विधानसभा चुनावों के हाल के चक्र के बाद जरूरत और भी बढ़ गयी है। हालांकि, इस चक्र में जिन पांच विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उनमें से केरल में भाजपा अपनी सारी कोशिशों के बावजूद, मुख्य मुकाबले से बाहर ही रही है और इस तरह, इंडिया ब्लाक से संबद्घ दो मोर्चों के बीच ही सत्ता का बदलाव हुआ है। जहां केरल में इसके बावजूद, भाजपा तीन सीटें जीतकर विधानसभा में प्रवेश पाने के अलावा भी अपना चुनावी प्रभाव बढ़ाने में कामयाब रही है, वहीं तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के नेतृत्ववाले गठजोड़ के हिस्से के तौर पर, उसकी सीटों तथा मत फीसद, दोनों में कमी ही हुई है।तीसरी दक्षिणी विधानसभा, पुड्डुचेरी में एनआर कांग्रेस का पल्लू पकड़कर भाजपा, दोबारा सत्ता तक पहुंचने में कामयाब रही है। जहां इस बार उनका बहुमत घटा है, वहीं इस बार भाजपा की सीटों तथा मत फीसद, दोनों में 2021 के चुनाव के मुकाबले गौर करने लायक गिरावट हुई है। दूसरी ओर, पूर्वी राज्य असम में भाजपा (अपने गठजोड़ के साथ) न सिर्फ तीसरी बार सत्ता में लौटी है बल्कि 2021 के चुनाव के मुकाबले सीटों तथा मत फीसद, दोनों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हुई ताकत के साथ सत्ता में लौटी है। इस तरह, विधानसभा चुनाव के इस चक्र में देश की सत्ता पर काबिज भाजपा ने कुल मिलाकर, देश की राजनीति और शासन पर, अपनी गिरफ्त को और मजबूत कर लिया है। यह 2024 के आम चुनाव में भाजपा को लगे अप्रत्याशित धक्के के बाद से, जिसमें भाजपा पूर्ण बहुमत से काफी पीछे, 240 के आंकड़े पर सिमट गयी थी और वह सरकार बनाने के लिए बिहार तथा आंध्र प्रदेश के अपने सहयोगियों पर निर्भर होकर रह गयी थी, एक के बाद एक विधानसभा चुनावों में जीत अपने नाम कर के, भाजपा द्वारा 2024 के जनता के फैसले के एक प्रकार से पलटे जाने के ही सिलसिले के जारी रहने को दिखाता है।बहरहाल, यह तो अपने आप में सिर्फ इतना ही इशारा करता है कि विपक्ष के लिए, भाजपा को चुनाव में हराना 2024 के मुकाबले और मुश्किल हो गया है। और इसलिए, विपक्षी ताकतों का एकजुट होना अब पहले से भी जरूरी हो जाता है। और विपक्षी एकजुटता में कोई भी दरार या कमजोरी, इस काम को और भी मुश्किल बना देगी। लेकिन, यह भी सिर्फ आधी सच्चाई है। बाकी आधी सच्चाई इसमें निहित है कि उक्त अप्रत्याशित धक्के के बाद से सत्ताधारी भाजपा की तिकड़मों ने, चुनावी हार–जीत के मानी ही बदल दिए हैं। उसने, चुनाव में बेहिसाब धन झोंकने तथा सरकारी मशीनरी समेत हर प्रकार के संसाधनों को अपने पक्ष में जोतने को ही अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंचाकर, चुनावी मैदान को पूरी तरह से नाबराबरी का ही नहीं किया है, चुनाव आयोग पर अपने पूर्ण नियंत्रण के जरिए, हर प्रकार के नियम–कायदों के अंकुश से भी पूरी तरह से छूट हासिल कर ली है। यहां तक कि उसने खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक प्रचार करने तथा धर्म के नाम पर वोट मांगने की भी खुली छूट हासिल कर ली है, जिसकी देश का चुनाव कानून सख्ती से मनाही करता है। चुनाव के इसी चक्र में खासतौर बंगाल तथा असम में तथाकथित श्घुसपैठियोंय से हिंदुओं के लिए खतरे की दुहाई का खुल्लमखुल्ला और नीचे से लेकर प्रधानमंत्री के स्तर तक इस्तेमाल, इसी का सबूत था। जाहिर है कि यह चुनाव को एक जनतांत्रिक चुनाव के बजाए, एक धार्मिक होड़ में ही बदलना है। लेकिन, दुर्भाग्य से झूठी चुनावी जीत गढ़ने का यह किस्सा, इतने पर ही खत्म नहीं हो जाता है। चुनाव आयोग की मिलीभगत से पहले हरियाणा में और फिर महाराष्टङ्ख में और दिल्ली में, मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में संदिग्ध नामों को जोड़ने और संभावित रूप से भाजपा–विरोधी नामों को काटने का खेल हुआ, जिसके संबंध में बाद में अनेक बड़े खुलासे भी हुए। इसके साथ ही, 2024 के आम चुनाव के साथ हुए ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों में, भाजपा और उसके सहयोगियों को इकतरफा जीत दिलाने के खेल के संबंध में भी अनेक खुलासे हुए। वास्तव में खुद 2024 के लोकसभा चुनाव में, मतदान के कई–कई दिनों बाद तक चुनाव आयोग के मत फीसद के आंकड़े बढ़ाते रहने को लेकर भी अनेक सवाल उठे, जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं।

सिस्टम न्याय, सत्ता और संवेदनाओं के बीच की बेचौनी

पंकज दुबे

भारतीय सिनेमा में अदालतों और न्याय व्यवस्था पर आधारित फिल्में हमेशा से दर्शकों को आकर्षित करती रही हैं। ऐसी फिल्मों की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे केवल कानूनी बहसों तक सीमित न रह जाएं, बल्कि इंसानी भावनाओं, सामाजिक यथार्थ और सत्ता की जटिलताओं को भी अपने भीतर समेट सकें। अश्विनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित नई हिंदी फिल्म शसिस्टम्य इसी चुनौती को स्वीकार करती है। आज के सिने–सोहबत में इसी फिल्म पर चर्चा करते हैं। शसिस्टम्य केवल एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की पड़ताल है जिसमें सच, शक्ति और विशेषाधिकार अक्सर एक–दूसरे से टकराते दिखाई देते हैं। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आशुतोष गोवारिकर जैसे अनुभवी कलाकार कहानी को अतिरिक्त वजन देते हैं। शसिस्टम्य की कहानी दो महिलाओं के इर्द–गिर्द घूमती है। एक ओर है नेहा राजवंश, जो विशेषाधिकार प्राप्त दुनिया से आने वाली सरकारी वकील है, और दूसरी ओर है सारिका रावत, जो अदालत की दुनिया में अपेक्षाकृत निचले पायदान पर खड़ी एक स्टेनोग्राफर है। दोनों अलग–अलग सामाजिक पृष्ठभूमियों से आती हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था के भीतर मौजूद असमानताओं और सत्ता के खेल से उनका सामना उन्हें एक साझा संघर्ष की ओर ले जाता है। फिल्म का मूल प्रश्न यही है कि क्या न्याय वास्तव में सबके लिए समान है, या फिर व्यवस्था केवल शक्तिशाली लोगों के पक्ष में काम करती है? निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी ने अपने करियर में अक्सर साधारण लोगों की असाधारण कहानियां कही हैं। शनिल बट्टे सन्नाटाय, शबरेली की बर्फीय और श्पंगाय जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे शहरों, पारिवारिक रिश्तों और व्यक्तिगत संघर्षों को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया था। शसिस्टम्य में वह पहली बार अपेक्षाकृत गहरे और गंभीर कोर्टरूम स्पेस में प्रवेश करती हैं। यह बदलाव दिलचस्प है क्योंकि यहां उनका परिचित मानवीय दृष्टिकोण तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ एक राजनीतिक और संस्थागत आलोचना भी जुड़ जाती है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका वातावरण है। अदालत की कार्यवाही, कानूनी प्रक्रियाएं और उनके पीछे छिपी शक्ति संरचनाएं काफी विश्वसनीय लगती हैं। कैमरा अक्सर पात्रों के चेहरों पर ठहरता है, जिससे उनके भीतर चल रहे संघर्ष दर्शकों तक पहुंचते हैं। कई दृश्यों में संवादों से अधिक मौन काम करता है। अश्विनी अय्यर तिवारी यहां शोर मचाने वाली फिल्म नहीं बनातींय वह दर्शकों को धीरे–धीरे उस दुनिया में ले जाती हैं जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जाती है। सोनाक्षी सिन्हा ने नेहा राजवंश के किरदार में अपने करियर के सबसे परिपक्व अभिनय में से एक दिया है। यह किरदार केवल एक वकील का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का है जो अपने विशेषाधिकारों और नैतिक जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई है। सोनाक्षी ने इस आंतरिक संघर्ष को बड़े संयम से निभाया है। कई जगह उनके चेहरे के भाव संवादों से अधिक प्रभाव पैदा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में श्दहाड़्य जैसी परियोजनाओं में उन्होंने जिस गंभीर अभिनय क्षमता का परिचय दिया था, शसिस्टम्य उसे और आगे बढ़ाती है। वहीं ज्योतिका फिल्म की भावनात्मक धुरी बनकर उभरती हैं। सारिका रावत के रूप में उनका प्रदर्शन अत्यंत स्वाभाविक और प्रभावशाली है। उनके किरदार में गुस्सा भी है, विवशता भी और आत्मसम्मान भी। ज्योतिका अपने अभिनय से यह महसूस करा देती हैं कि व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर खड़े लोग किस तरह रोज अन्याय का सामना करते हैं। कई दृश्यों में उनका अभिनय फिल्म को नई ऊंचाई देता है। अशुतोष गोवारिकर का काम भी उल्लेखनीय है। उनका अनुभव स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है। वह कहानी में स्थिरता और गंभीरता जोड़ते हैं। सहायक कलाकारों ने भी अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया है, जिससे फिल्म का संसार विश्वसनीय बनता है। फिल्म का लेखन महत्वाकांक्षी है। यह केवल एक मुकदमे की कहानी नहीं कहना चाहता, बल्कि पूरे न्यायिक ढांचे पर टिप्पणी करना चाहता है। कई दृश्य ऐसे हैं जहां फिल्म महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि क्या कानून और न्याय एक ही चीज हैं? क्या सच हमेशा अदालत में जीतता है? क्या सामाजिक हैसियत फैसलों को प्रभावित करती है? इन प्रश्नों के कारण फिल्म विचारोत्तेजक बनती है। हालांकि, यहीं फिल्म की कुछ कमजोरियां भी सामने आती हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि फिल्म के पास अच्छे विचार तो हैं, लेकिन वह उन्हें पूरी गहराई तक विकसित नहीं कर पाती। कुछ उपकथाएं अधूरी लगती हैं और कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष सतही स्तर पर ही रह जाते हैं। कोर्टरूम ड्रामा के रूप में फिल्म कई बार उतनी तीखी नहीं बन पाती जितनी उसकी विषयवस्तु मांग करती है। फिल्म का दूसरा भाग विशेष रूप से मिश्रित प्रभाव छोड़ता है। शुरुआती हिस्से में जो रहस्य और तनाव निर्मित होता है, वह बाद में थोड़ी गति खो देता है। कुछ दृश्य अनावश्यक रूप से लंबे महसूस होते हैं। दर्शकों को यह भी लग सकता है कि फिल्म अपने सबसे साहसी राजनीतिक निष्कर्षों तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है। व्यवस्था की आलोचना मौजूद है, लेकिन वह कई बार सुरक्षित दायरे में रहती है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म का कैमरावर्क काफी प्रभावशाली है। अदालतों के बंद कमरों, गलियारों और वेटिंग क्षेत्र को जिस तरह फिल्माया गया है, वह कहानी के दबाव और घुटन को महसूस कराता है। बैकग्राउंड स्कोर भी संयमित है। संगीत कभी भी कहानी पर हावी नहीं होता, बल्कि उसके भावनात्मक स्वर को मजबूत करता है। शसिस्टम्य की एक और विशेषता इसकी महिला दृष्टि है। यह फिल्म महिलाओं को केवल पीड़ित या आदर्शवादी पात्रों के रूप में नहीं दिखाती। यहां महिलाएं जटिल हैं, महत्वाकांक्षी हैं, गलतियां भी करती हैं और कठिन फैसले भी लेती हैं। अश्विनी अय्यर तिवारी का यह दृष्टिकोण हिंदी सिनेमा में अक्सर दिखाई नहीं देता। फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यही है कि वह अपने महिला पात्रों को पूर्ण मनुष्य की तरह प्रस्तुत करती है। अश्विनी अय्यर तिवारी के फिल्मी सफर को देखें तो शसिस्टम्य उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह दिखाई देती है। यह उनकी सबसे परिपक्व या सबसे प्रभावशाली फिल्म नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी रचनात्मक महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। वह अपने परिचित भावनात्मक क्षेत्र से बाहर निकलकर एक बड़े सामाजिक और संस्थागत विषय को छूने की कोशिश करती हैं। यह प्रयास सम्मान के योग्य है, भले ही परिणाम पूरी तरह निर्दोष न हो। मिलाजुला कर शसिस्टम्य ऐसी फिल्म है जो अपने विचारों की वजह से याद रहती है, भले ही हर जगह समान रूप से प्रभावशाली न हो। यह दर्शकों को आसान जवाब नहीं देती, बल्कि उन्हें सवालों के साथ छोड़ती है। न्याय, सत्ता और नैतिकता के बीच मौजूद जटिल संबंधों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका के मजबूत अभिनय, अश्विनी अय्यर तिवारी की संवेदनशील दृष्टि और फिल्म का सामाजिक सरोकार इसे देखने योग्य बनाते हैं। यदि आप तेज रफ्तार थ्रिलर की उम्मीद लेकर बैठेंगे तो शायद शसिस्टम्य आपको पूरी तरह संतुष्ट न करे। लेकिन अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो समाज और व्यवस्था के भीतर छिपी परतों को खोलने की कोशिश करती हैं, तो यह फिल्म आपके समय की हकदार है। यह एक परफेक्ट कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, लेकिन एक ईमानदार और विचारशील सिनेमाई प्रयास अवश्य है।

तानाशाही बंद करे सरकार नहीं तो पूरे देश का व्यापारी रोड पर उतरेगा : अंजनी कुमार पाण्डेय

लखनऊ। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल पश्चिम विधानसभा लखनऊ का गठन एवं शपथ समारोह राष्ट्रीय सचिव प्रवीण मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियो का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न कराया गया नीरज यादव विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रपाल गौड संरक्षक श्रीपाल गौड महासचिव मनोज तिवारी उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कोषाध्यक्ष राम शंकर मिश्र विधि सलाहकार अखिल चौधरी संगठन मंत्री सुयॅकेश कुमार सचिव सचिन गुप्ता वरिष्ठ मंत्री बबलू उपाध्याय सलाहकार हरि दर्शन श्रीवास्तव संयुक्त मंत्री अरविंद पाल वरिष्ठ संगठन मंत्री चंदन गौड़ मंत्री तालिब सिद्दीकी प्रचार मंत्री आदि को संगठन के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे ने शपथ दिलाई साथ में अयोध्या रोड अध्यक्ष रतन दास को प्रमोट करके प्रदेश प्रभारी बनाया गया। इस मौके पर उपस्थित संगठन के पदाधिकारी गण राष्ट्रीय वरिष्ठ सचिव हरिओम दुबे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नाथ मिश्रा प्रदेश महासचिव राम तिवारी लखनऊ मंडल अध्यक्ष अंकुर मिश्रा महासचिव मनीष सिंह जिला उपाध्यक्ष नितिन सचान नगर संगठन मंत्री अमित निगम ट्रांसपोर्ट नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता पारा अध्यक्ष धर्मराज यादव हंस खेड़ा उपाध्यक्ष अंगद सिंह अयोध्या रोड उपाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद संगठन मंत्री देव वर्मा इत्यादि बड़ी संख्या में व्यापारी एवं पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियो को बधाई देते हुए कहा संगठन हर सुख दुख में व्यापारियों के साथ खड़ा है। सरकार लगातार बिजली डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ा रही है ज्वेलरी के व्यापारियों का कारोबार प्रधानमंत्री के बयान के बाद बहुत खराब हो गया है संगठन सरकार कि व्यापारी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए घोर विरोध निंदा करता है यह सरकार को बताना चाहता हूं कि तानाशाही बंद करें नहीं तो पूरे देश का व्यापारी रोड पर उतरेगा यदि संविधान को सरकार मानती है तो लोकतंत्र अभी जिंदा है मार्केट में सन्नाटा छाया है व्यापारी भुखमरी के कगार पर है।

संदीप सिंह हत्याकांड पर बोले अजय राय, कहा- कानून व्यवस्था ध्वस्त, 2027 में जनता करेगी भाजपा की विदाई : अजय राय

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय बुधवार को जौनपुर पहुंचे और लखनऊ में हत्या के शिकार हुए प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पत्रकारों से बातचीत में अजय राय ने कहा कि संदीप सिंह जौनपुर के निवासी थे और रोजगार के सिलसिले में लखनऊ गए थे, जहां दिनदहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का बड़ा उदाहरण है। राय ने आरोप लगाया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हत्याएं, अपराध और महिलाओं के खिलाफ घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार अपराध रोकने में विफल साबित हो रही है। अजय राय ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई वीडियो के आधार पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन वह जनता के मुद्दे उठाना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है और अब लोग सरकार की नीतियों को समझ चुके हैं। संदीप सिंह के परिजनों ने भी हत्याकांड की निष्पक्ष और ठोस जांच की मांग उठाई। परिवार का कहना है कि मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन घटना में शामिल शूटर और अन्य आरोपियों की पूरी भूमिका अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजनों ने मांग की कि मामले में शामिल सभी अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अजय राय ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और लोकतांत्रिक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रदेश की दिशा तय करेगी। साथ ही उन्होंने संदीप सिंह हत्याकांड समेत अन्य गंभीर मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग दोहराई।इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह शहर अध्यक्ष आरिफ खान प्रभारी मंगला मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विकेश उपाध्याय वरिष्ठ नेता राकेश कुमार सिंह डब्बू सभासद शाहनवाज हुसैन ,राज कुमार गुप्ता,अनिल दुबे आजाद आदि मौजद रहे।

टीजीटी परीक्षा केंद्रों का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, निष्पक्ष व पारदर्शी परीक्षा कराने के दिए निर्देश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने बुधवार को विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने टीडी कॉलेज आर्ट फैकल्टी, टीडी लॉ कॉलेज तथा टीडी इंटर कॉलेज पहुंचकर परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों एवं संबंधित अधिकारियों से परीक्षा संचालन की तैयारियों और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही परीक्षा की गोपनीयता, सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि परीक्षा पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं सुचारु व्यवस्था के साथ संपन्न कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रों पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। सुरक्षा, निगरानी एवं अन्य आवश्यक प्रबंध आयोग के मानकों के अनुरूप मिले, जिस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि.ध्रा.) परमानंद झा, संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापक तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो कुंतल प्रतिबंधित दोहरा बरामदय दो आरोपी गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग दो कुंतल प्रतिबंधित दोहरा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव एवं सहायक पुलिस अधीक्षकध्क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 जून मंगलवार को चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान थाना क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी मस्जिद, रौजा अर्जन से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले का बुधवार को खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शहर आयुश श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से करीब दो कुंतल प्रतिबंधित दोहरा बरामद हुआ। बरामद सामग्री को आवश्यक जांच के लिए खाद्य निरीक्षक के सुपुर्द कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन साहू पुत्र अजय कुमार साहू तथा विवेक साहू पुत्र अजय कुमार साहू निवासी बड़ी मस्जिद, रौजा अर्जन, थाना कोतवाली जौनपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कारोबारियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सूर्या चौहान हत्याकांड के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग, आईएचपी व राष्ट्रीय बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की जौनपुर इकाई ने गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बुधवार को जिलाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि बकरीद के दिन गाजियाबाद में सूर्या चौहान की निर्मम हत्या से समाज में गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त है। इस घटना ने प्रदेशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। संगठन ने मामले में एक आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री एवं पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि इससे प्रदेश की जनता का कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास मजबूत हुआ है। जिलाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने मांग की कि हत्या में शामिल शेष सभी आरोपियों तथा इस अपराध के षड्यंत्र में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए, जो समाज में एक मजबूत संदेश दे और भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की जघन्य घटना को अंजाम देने का साहस न कर सके। संगठन ने कहा कि निर्दोष युवक की हत्या करने वाले सभी दोषियों को उनके अपराध के अनुरूप सख्त सजा देकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाना चाहिए। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस अवसर पर कृष्ण कुमार उपाध्याय, यादवेन्द्र यादव, जितेंद्र बहादुर सिंह सहित संगठन के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जौनपुर में TGT परीक्षा आज से, 20 केंद्रों पर 6,831 अभ्यर्थी देंगे परीक्षाय नकल पर सख्त पहरा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में 3 और 4 जून बुधवार , गुरुवार को आयोजित होने वाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (ज्ळज्) परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को पूर्णतः नकलविहीन, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर कुल 6,831 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। प्रत्येक गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या नकल की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इस मामले में अपर जिलाधिकारी परमानन्द झा ने बताया कि जिला प्रशासन ने परीक्षा संचालन के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है। अधिकारियों को परीक्षा के दौरान लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान नकल, अनुचित साधनों के प्रयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने तथा निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भारत–नेपाल सीमा पर चालकों और एजेंट की हड़ताल, आयात–निर्यात पूरी तरह ठप, फंसे 200 से ज्यादा ट्रक

लखनऊ, (संवाददाता)। भारत–नेपाल सीमा पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर अव्यवस्थाओं के विरोध में सोमवार को कस्टम हाउस एजेंटों, क्लीयरिंग एजेंटों और ट्रक चालकों ने कार्य बहिष्कार कर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी। इससे सीमा पार आयात–निर्यात पूरी तरह ठप हो गया और आईसीपी परिसर में 200 से अधिक ट्रक फंस गए। प्रदर्शनकारियों ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) प्रबंधन पर मनमानी, अभद्र व्यवहार और बुनियादी सुविधाएं न देने का आरोप लगाया। सीमा शुल्क आयुक्त को भेजे ज्ञापन में कहा गया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पार्किंग पास जारी करने में देरी, गेट पास की जटिल प्रक्रिया और कर्मचारियों की कार्यशैली से ट्रांसपोर्टरों व निर्यातकों को रोजाना भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्लीयरिंग एजेंटों का कहना है कि पहले व्यवस्थाएं सुचारु थीं, लेकिन नई प्रबंधन व्यवस्था के बाद समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपये की लागत से बने आईसीपी का संचालन मनमाने तरीके से किया जा रहा है, जिससे भारत–नेपाल व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारी विजय जायसवाल ने बताया कि नेपाल जाने वाले पेट्रोलियम टैंकरों की निकासी में पहले दो घंटे लगते थे, लेकिन अब आठ घंटे से अधिक समय लग रहा है। भीषण गर्मी में डीजल, पेट्रोल और गैस से भरे दर्जनों टैंकर खड़े रहने से हादसे का खतरा बढ़ गया है।

संक्षिप्त खबरें

पेट्रोल–डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त हुए मंत्री

लखनऊ, (संवाददाता)। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, पारदर्शी वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सोमवार को बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों, खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की।बैठक में मंत्री ने विशेष रूप से नेपाल और बिहार की सीमाओं से सटे जनपदों में पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी तथा कालाबाजारी की शिकायतों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वास्तविक उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से तेल को सीमावर्ती क्षेत्रों अथवा अन्य राज्यों में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी गतिविधियां किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं।मनोज कुमार पाण्डेय ने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों की तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर जमाखोरी, कृत्रिम अभाव पैदा करना, घटतौली या उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए सभी जनपदों में नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए।बैठक में घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस आपूर्ति व्यवस्था के विस्तार की भी समीक्षा की गई।

सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने जेईई और बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम

लखनऊ, (संवाददाता)। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। विद्यार्थियों की इस उल्लेखनीय सफलता पर समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सभी सफल छात्र–छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे. राम ने बताया कि मिर्जापुर के मड़िहान स्थित सर्वोदय विद्यालय को डॉ. अरुण कुमार तिवारी ट्रस्ट, एक्स नवोदयन फाउंडेशन और एक निजी बीमा कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व सहयोग से अभियंत्रण और चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसी पहल का परिणाम है कि इस वर्ष विद्यालय के 11 विद्यार्थियों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) में सफलता प्राप्त की है।मड़िहान सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं दामिनी पटेल, अंबाला वर्मा, सृष्टि, शिवानी और रागिनी ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) में सफलता हासिल की, जबकि प्रीति ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (उन्नत) के लिए भी पात्रता प्राप्त की। प्रीति और दामिनी का चयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी हुआ है।

प्रदेश में संग्रहालयों के विकास को मिली रफ्तार, विभिन्न परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए संचालित संग्रहालय विकास योजनाओं को गति देते हुए विभिन्न जनपदों में निर्माणाधीन संग्रहालयों और स्मृति स्थलों के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि जारी की है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रंपअममत ैपदही ने बताया कि संग्रहालय निदेशालय के अधीन संचालित परियोजनाओं के लिए अप्रैल 2026 तक आवश्यक धनराशि की प्रथम किश्त कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। किसी भी प्रकार की निम्नस्तरीय सामग्री के प्रयोग पर संबंधित संस्था के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।मंत्री ने बताया कि टंतंदेंप के लमही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय में आंतरिक सज्जा, प्रदर्शन व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। वहीं थ्पतव्रंइंक में कांच संग्रहालय के विकास और प्रदर्शन व्यवस्था के लिए 4 करोड़ 40 लाख 54 हजार रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।इसी प्रकार क्मवतपं में पुरानी कचहरी परिसर स्थित शहीद रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति स्थल के विकास, प्रदर्श व्यवस्था और आंतरिक सज्जा के लिए 30 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। यह परियोजना स्वतंत्रता संग्राम और क्षेत्रीय इतिहास से जुड़ी स्मृतियों को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।पर्यटन मंत्री ने बताया कि राजधानी स्नबादवू स्थित संग्रहालय में सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और उन्नयन कार्यों के लिए भी पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की गई है।

पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित विभागीय योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में विभागीय स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए तथा व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए।नरेंद्र कश्यप ने शासकीय विशेष विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों के अभाव में विद्यालयों का उद्देश्य प्रभावित होता है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थायी नियुक्तियां होने तक संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने संकेत, स्पर्श, ममता और प्रयास जैसे विशेष विद्यालयों में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराने तथा इसके लिए अलग से नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।

ट्रेन की बोगी पर चढ़ कर आरपीएफ व जीआरपी को घटे छकाया सिरफिरा

अयोध्या। एक सिरफिरे युवक ने बुधवार की सुबह जम्मू की ओर जाने वाली सियालदह एक्सप्रेस की बोगी पर चढ़कर जीआरपी व आरपीएफ को खूब छकाया।हालांकि जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों के काफी मशक्कत और सूझबूझ के चलते बिना किसी नुकसान उसे बोगी से सुरक्षित उतार लिया गया। जिसके चलते एक बड़ी घटना होने से टल गई।जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।यह वायरल वीडियो शहर के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है,जहां एक सिरफिरा युवक जम्मू को जाने वाली सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी पर चढ़ गया और हाइटेंशन तारों के बीच दौड़ने लगा।युवक की इस हरकत से यात्रियों में आफर तफरी मच गई वहीं जीआरपी पुलिस और आरपीएफ भी मौके पहुंच गई।कोई अनहोनी न हो इसको लेकर रेलवे की और से विद्युत सप्लाई बंद कर दी गई।सिरफिरे युवक की इस हरकत से सभी सकते में आ गए और जीआरपी पुलिस आरपीएफ की टीम ने उसे ट्रेन की बोगी से सकुशल उतारने की कवायद शुरू कर दी,हालांकि काफी देर तक चले इस घटनाक्रम में सभी पसीने छूट गए।जीआरपी पुलिस और आरपीएफ की टीम उस युवक को समझाने बुझाने में लग गई और कड़ी मशक्कत के बाद उसे सकुशल ट्रेन की बोगी से नीचे उतार लिया, तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।हालांकि पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्रेन करीब 45 मिनट तक रुकी रही, युवक को सकुशल उतारने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक जीआरपी अनिल प्रकाश सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही ने बताया कि परिजनों के मुताबिक उक्त युवक कुछ परेशान था।उसकी पहचान सोनू कुमार रामघाट के रूप में हुई है।उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बनी प्रज्ञा पाण्डेय

अयोध्या।बुधवार को नवागत समाज कल्याण अधिकारी के रूप में प्रज्ञा पाण्डेय ने अपना कार्यभार ग्रहण किया इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया।तत्पश्चात उन्होंने सभी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया।बताया कि शासन के मंशानुरुप कार्य करना उनकी प्रथम प्राथमिकता है।कौशांबी से स्थानांतरित होकर आई नवागत जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा पाण्डेय ने बताया कि वृद्धावस्था, विधवा पेंशन के लाभार्थियों को लाभ दिलाना रहेगा।साथ ही साथ सभी पात्र छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शैक्षिक सहायता प्रदान करना है।वहीअनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।बताया कि प्रयास यही रहेगा कि समाज मे कमजोर, गरीब एवं वंचित वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का प्रभावी संचालन करना है।बताया कि समाज मे रह रही महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।कहा कि गरीब,असहाय और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा,जनकल्याणकारी योजनाओं को घर–घर पहुंचाया जाएगा जिसके चलते समाज में रह रहे सभी पात्रों को शासन द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।

15 जून तक जमा करें पत्र दो प्रति में फॉर्म - डीएम

अयोध्या।दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता' के तहत अनुदान हेतु आवेदक 15 जून तक दो प्रतियों में कार्यालय– जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,अयोध्या में जमा कर सकते है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि इस समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) हेतु ''दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता'' योजना निम्नलिखित 07 परियोजनाओंध कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है।बताया कि अर्ली इण्टरवेंशन सेन्टर,डे केयर सेण्टरध प्री–प्राईमरी स्कूल, प्राईमरी स्कूल स्तर तक के विद्यालयों का संचालन, जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन,कौशल विकास (अधिकतम 04 ट्रेड तथा न्यूनतम 02 ट्रेड) पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन हो।बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो सम्बन्धित क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखतें हो,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 की वेबसाईट पर योजना से सम्बन्धित कार्यकारी आदेशधदिशा–निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप कर सकते है।इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं ''दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता'' योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम दिनांक 15.06.2026 तक दो प्रतियों में कार्यालय– जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अयोध्या में जमा कर सकते है।

'गन्ना किसानों की खुशहाली का आधार बनी समयबद्ध भुगतान व्यवस्था'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गन्ना क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों, पारदर्शी कार्यप्रणाली तथा तकनीक आधारित व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप गन्ना किसानों को उनकी उपज का मूल्य समयबद्ध रूप से प्राप्त हो रहा है। जनपद शाहजहांपुर में गन्ना विकास एवं गन्ना मूल्य भुगतान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। जनपद शाहजहाँपुर में गन्ने की फसल का आच्छादन लगभग 1,03,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है। गन्ना विकास विभाग द्वारा रोजा, निगोही, पुवायाँ एवं तिलहर गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से विभिन्न गन्ना विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। सहकारी गन्ना विकास समिति रोजा एवं पुवायाँ तथा चीनी मिल समिति तिलहर द्वारा लगभग 1.96 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक सदस्यों के गन्ना विपणन एवं कृषि निवेश उपलब्धता की कार्यवाही की जाती है। जनपद में कुल पाँच चीनी मिलें संचालित हैं, जिनमें तिलहर एवं पुवायाँ सहकारी क्षेत्र की तथा निगोही, रोजा एवं मकसूदापुर निजी क्षेत्र की चीनी मिलें शामिल हैं। ये चीनी मिलें गन्ना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं तथा गन्ना खरीद एवं मूल्य भुगतान की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित कर रही हैं। पेराई सत्र 2025–26 में जनपद की चीनी मिलों पर 1029.11 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य देय हुआ, जिसके सापेक्ष 923.60 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। यह कुल देय गन्ना मूल्य का 89.75 प्रतिशत है। जनपद की चीनी मिल निगोही, रोजा, तिलहर एवं पुवायाँ द्वारा कृषकों के शत–प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। यह उपलब्धि किसानों के प्रति चीनी मिलों की प्रतिबद्धता तथा प्रभावी भुगतान व्यवस्था को दर्शाती है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान उपलब्ध कराने के साथ–साथ विभाग द्वारा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्नत प्रजातियों के प्रचार–प्रसार, कृषि निवेश की उपलब्धता तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ किसानों की आय में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। गन्ना क्षेत्र में हुए इन सकारात्मक परिवर्तनों का प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। किसानों की बढ़ी हुई आय से स्थानीय बाजारों में व्यापारिक गतिविधियों को बल मिला है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को नई दिशा प्राप्त हुई है। गन्ना विकास विभाग और चीनी मिलों के समन्वित प्रयासों से किसानों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद में गन्ना विकास एवं गन्ना मूल्य भुगतान के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियाँ यह सिद्ध करती हैं कि किसान हितैषी नीतियाँ, प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था तथा समयबद्ध भुगतान प्रणाली किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। भविष्य में भी किसानों की आय वृद्धि, उत्पादन क्षमता में सुधार तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे।

विकास कार्यों में लापरवाही पर कमिश्नर नाराज

गोरखपुर, (संवाददाता)। कमिश्नर अनिल ढींगरा ने सीएमआईएस और सीएम डैशबोर्ड के आंकड़ों के आधार पर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। कार्य में लापरवाही के चलते पोर्टल पर रेड श्रेणी में पाए जाने पर तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कमिश्नर ने सीमांकन से संबंधित न्यायिक कोर्ट के लंबित वादों के निपटारों के देरी चलते गोरखपुर सदर तहसीलदार, एवं देवरिया में तीन महीनों में कुपोषित बच्चों के सुधार का प्रतिशत कम मिला। कमिश्नर ने दोनों एक्सईएन और गोरखपुर व देवरिया के जिला कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने लंबित न्यायिक वादों के निस्तारण की समीक्षा की। धारा–24 (सीमांकन) के वादों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि एसडीएम

देवरिया एसडीएम सहित 14 अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। आयुक्त सभागार में सोमवार को हुई बैठक में मंडल स्तरीय विकास कार्यों, निर्माण परियोजनाओं, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के प्रगति की मासिक समीक्षा हुई। यूपी आरएनएसएस की पांच परियोजनाएं और यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की छह परियोजनाएं रेड श्रेणी में दिखने पर एक्सईएन जवाब नहीं दे पाए। इसके अलावा गोरखपुर कैंपियरगंज, गोला, देवरिया सदर, भाटपाररानी और एडीएम प्रथम व द्वितीय देवरिया, अतिरिक्त उप जिलाधिकारी देवरिया के न्यायालय में अत्यधिक वाद लंबित है। निस्तारण में देरी पर सभी का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार धार–34 (नामांतरण) के वादों की समीक्षा 3 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक समय से वाद तहसीलदार सदर गोरखपुर, तहसीलदार न्यायिक सदर गोरखपुर, तहसीलदार न्यायिक सदर देवरिया, नायब तहसीलदार कैंपियागंज, पिपराइच, रामपुर कारखाना, भटनी के स्तर पर लंबित पाया गया। कमिश्नर ने सभी के वेतन बाधित करने के निर्देश दिए। जिले में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा करते कमिश्नर ने सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई और सुधार न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। चार फाटक असुरन मार्ग, मानीराम–बालापार मार्ग एवं गोरखपुर–पिपराईच मार्ग के सुस्त निर्माण कार्य तथा एचएन सिंह चौराहा से हड़हवा फाटक होते हुए गोरखनाथ मंदिर तक जाने वाले मार्ग के कार्य में जल निगम एवं लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड–3 के कार्यों में तेजी न आने पर तीन अभियंताओं पर नाराजगी जताई। कहा कि सुधार न होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। विरासत गलियारा में भी कार्य की धीमी प्रगति पर निर्माण खंड–2 के एक्सईएन और एई को फटकार लगाई। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय से संबंधित आडिटोरियम के निर्माण में देरी पर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सचेत किया। गोड़धोइया नाला एवं रामगढ़ताल के जीर्णोद्धार तथा वाटर ट्रीटमेंट के कार्य में विलंब जल निगम के चीफ इंजीनियर, एसई, एक्सईएन को कड़ी फटकार लगाई।

दो दिन में चार डिग्री चढ़ा पारा, दो जून तक येलो अलर्ट जारी

भदोही, (संवाददाता)। जिले में दो दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। दो दिन में चार डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। रविवार को अधिकतम पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने दो जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम कभी खराब हो सकता है। जिला प्रशासन ने एडवाइजारी करके बताया कि दो जून तक खराब मौसम बने रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान वज्रपात (बिजली), मेघगर्जन तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने अपील की है कि हर कोई सतर्कता एवं सावधानी बरतें। बिना जरूरत के घरों से बाहर निकलने से बचें। येलो अलर्ट का मतलब है कि खतरे के प्रति सतर्क रहना है। वर्तमान में कोई खतरा नहीं है, लेकिन मौसम कभी खराब हो सकता है।

46 किलोमीटर के हाईवे पर स्वच्छता बेपटरी, 14 जगहों पर नाले में कचरे का कब्जा

भदोही, (संवाददाता)। मानसून सीजन में 20 दिन बचे हैं। हाईवे के 46 किलोमीटर के दायरे में दोनों पटरियों पर 14 जगहों पर नाले जाम हैं। गिराई और माधोसिंह बाजार में नाला ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सर्विसलेन पर बह रहा है। बाजार और आबादी वाले इलाकों में नालियां चोक हैं। गिराई के पास तो नाले का पानी बिजली उपकेंद्र में घुस जाता है। नेशनल हाईवे प्राधिकरण के अनुसार, राजातालाब–हंडिया खंड के 72 किलोमीटर हाईवे के 46 किमी दायरा भदोही की सीमा से होकर गुजरता है। हाईवे पर जंगीगंज, कौलापुर, गोपीगंज, घोसिया, औराई, बाबूसराय और महराजगंज जैसे प्रमुख बाजार हैं। एनएचएआई की ओर से बारिश के पानी की निकासी के लिए हाईवे के दोनों तरफ नाले बनाए गए हैं। नालों को कई जगहों पर खुला छोड़ दिया गया है। हाईवे पर नाले कचरे से पट गए हैं।

संक्षिप्त खबरें

बीएड प्रवेश परीक्षा में इतिहास, भूगोल के प्रश्नों में उलझे अभ्यर्थी

भदोही, (संवाददाता)। वहीं गणित, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन के प्रश्न को आसानी से हल कर लिए। जिले के छह केंद्रों पर रविवार को आयोजित परीक्षा में 90 फीसदी अभ्यर्थी उपस्थिति रहे। पहली पाली की परीक्षा में भाषा और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे गए, जबकि दूसरी पाली में प्रश्न पत्र में जनरल एप्टीट्यूड और विषय (विज्ञानध्वाणिज्यध्कृषि) से जुड़े प्रश्न थे। काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय, विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज, जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज ज्ञानपुर समेत अन्य केंद्रो पर सुबह सात बजे से अभ्यर्थी और उनके अभिभावक पहुंच गए थे। सुबह आठ बजे गहन जांच के बाद अभ्यर्थियों को कक्ष में को प्रवेश दिया गया। पहली पाली में सुबह नौ से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली में दोपहर दो से पांच बजे तक परीक्षा हुई। दोनों पालियों में नामित अफसरों ने केंद्रों की व्यवस्था देखी। एनआईसी के कंट्रोल रूम से भी केंद्रों की निगरानी की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि पहली पाली में पंजीकृत 2884 में से 2681 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दूसरी पाली में भी उन्हीं अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बताया कि 90 फीसदी से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है।

15 साल से नॉर्थ–ईस्ट तक असलहे की तस्करी कर रहे पूर्वांचल के बदमाश

वाराणसी, (संवाददाता)। जरायम की दुनिया में पूर्वांचल का नाम 90 के दशक से चल रहा है। 40 साल तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में पूर्वांचल के शूटरों के बिना कोई वारदात नहीं होती थी। पिछले 15 साल से पूर्वांचल के बदमाशों ने ही यूपी–बिहार से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक मादक पदार्थों और असलहों की तस्करी की कमान संभाल रखी है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को पूर्वांचल के शूटरों ने अंजाम दिया था। बलिया के राजकुमार सिंह, नवीन सिंह और गाजीपुर के विनय राय को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बिहार और बलिया के शूटरों ने मिलकर बंगाल में इस हत्या को अंजाम दिया था। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में भी हत्या और अपहरण जैसी वारदातों को पूर्वांचल के ही बदमाशों ने अंजाम दिया। दो दिन पहले झारखंड में बैंक डकैती कांड में गोरखपुर, मऊ और गाजीपुर के बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई, सूरत और अहमदाबाद में बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद पूर्वांचल के बदमाश यूपी और पूर्वांचल की ओर रुख करते हैं। 40 साल के रिकॉर्ड को देखें तो मुंबई में अपराध करने वाले पूर्वांचल के कई चर्चित चेहरे रहे हैं। इनमें कुछ नेता बने, कुछ बिल्डर और कुछ दुनिया से अलविदा हो गए। मुंबई में जितनी भी चर्चित आपराधिक घटनाएं हुईं, उनमें पूर्वांचल के बड़े चेहरों की गिरफ्तारी हुई।

पेपर लीक को लेकर युवाओं से आप सांसद संजय सिंह ने किया संवाद

प्रयागराज, (संवाददाता)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज प्रयागराज पहुंचे। जहां उन्होंने छात्रों के साथ लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों से लेकर भर्ती प्रक्रिया में हो रहे घोटाले तक के सभी विषयों को लेकर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों की समस्याएं भी सुनी और उन्होंने सरकार से कहा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 आंदोलन होंगे और सरकार अब तैयार रहे क्योंकि छात्र शक्ति जब जागेगा तो उसके तूफान में सरकार की दमनकारी नीतियां पूरी तरीके से उड़ जाएगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इसमें 4 वर्षों में अलग–अलग मानकों में कुल 77 भर्तियों में घोटाले देखने को मिले जो कि छात्र शक्ति और उनके मनोबल को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने किया है। सर्किट हाउस में प्रतियोगी छात्रों से आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह संवाद कर रहे थे। संवाद के दौरान सभागार में अपर जिलाधिकारी (एडीएम) सिटी सत्यम मिश्रा और डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य पहुंच गए। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने आप सांसद संजय सिंह से किनारे चलकर बात करने को कहा। इस पर संजय सिंह भड़क गए और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा कि जिस परीक्षा पर हो रही चर्चा को आप रोकने के लिए आए हैं वही परीक्षा पास करके आप अधिकारी बने हैं। सांसद संजय सिंह अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने कहा कि क्या मैं कानून व्यवस्था भंग कर रहा हूं, जो आप मुझे रोकने आए हैं। आपको सर्किट हाउस के अंदर आने का अधिकार ही न हीं है। अगर में सार्वजनिक स्थान या सड़क पर कोई कार्यक्रम करता तो आप एक बार रोक सकते थे। कहा कि आप सांसद के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। इसकी शिकायत मैं प्रिविलेज कमेटी से करूंगा। एडीएम सिटी के सभागार में पहुंचने के दौरान बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सांसद संजय सिंह ने एडीएम और डीसीपी से कहा कि सर्किट हाउस आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। यह जनता के पैसे से बना है। बंद कमरे में क्या हो रहा है यह देखना आपका काम नहीं है। यहां पर कोई देश विरोधी बात हो रही है क्या। यहां परीक्षाओं में पेपर लीक पर चर्चा हो रही है। क्या लोकतंत्र में इस पर बात करना गुनाह है। यह पहली बार देख रहा हूं कि प्रशासन कह रहा है कि पेपर लीक पर बात मत करिए। लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है और बात नहीं की जाएगी।

भोजवाल समाज ने की अन्नकला बोर्ड गठन की मांग चौधरी सम्मान समारोह आयोजित

प्रयागराज, (संवाददाता)। भोजवाल फाउंडेशन द्वारा भोजवाल (भुर्जी) समाज का भोजवाल चौधरी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के भोजवाल समाज के चौधरी, मनोनीत सभासद, पत्रकार, अधिवक्ता, अध्यापक एवं हाल ही में चयनित पीसीएस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष अरुण भोजवाल आजाद ने प्रदेश सरकार से एक करोड़ भोजवाल समाज के लिए श्री अन्नकला बोर्ड गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बोर्ड बनने से समाज के लगभग एक करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। प्रदेश कोषाध्यक्ष इंजीनियर उमाशंकर भोजवाल ने कहा कि सरकार जल्द बोर्ड का निर्माण करे ताकि योजनाओं का लाभ पूरे समाज तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन जल्द ही 403 विधानसभाओं में भोजवाल जागरूकता अभियान चलाएगा।

पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में दुष्कर्म के आरोपी को दबोचा

वाराणसी, (संवाददाता)। मऊ जिले की हलधरपुर पुलिस द्वारा सोमवार की देर रात नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी दानिश उर्फ छोटू को मडैली बढनपुरा गांव के पास हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। एसपी कमलेश बहादुर ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस की दो टीमों ने घेराबंदी की थी। आरोपी स्थानीय थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव निवासी है। उसके द्वारा एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना की गई थी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस टीम के रोकने पर आरोपी द्वारा फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो उसके पैर के घुटने के नीचे लगी। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, एक कारतूस बरामद किया।

राहगीरों को पीटकर खास तरीके से ट्रांसफर कराते थे रकम

वाराणसी, (संवाददाता)। राहगीरों की पिटाई कर मोबाइल लूटने और गेमिंग ऐप के जरिए रकम ट्रांसफर कराने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को सारनाथ पुलिस ने सोमवार को हृदयपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बाइक और 2510 रुपये नकद बरामद किए गए। एडीसीपी वरुणा लिपि नागायच ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में चोलापुर के टिसौरा निवासी अनीश कुमार चौबे उर्फ विशाल, सिंधोरा के मवईया निवासी धीरज यादव उर्फ गोलू और चोलापुर के मुरली निवासी अनिकेत यादव उर्फ गोलू शामिल हैं। 31 मई की रात आरोपियों ने सिंहपुर रिंग रोड पर एक बाइक सवार युवक को रोक लिया और उसकी पिटाई करने के बाद उसके मोबाइल से फोनपे के जरिए 91 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। पूछताछ में अनीश चौबे ने बताया कि रकम सीधे बैंक खाते में न मंगाकर ऑनलाइन गेम श्एविएटरश के खाते में ट्रांसफर कराई जाती थी, ताकि पुलिस आसानी से उन तक न पहुंच सके। उसने बताया कि बाद में गेमिंग खाते से रकम वापस निकाल ली जाती थी और आपस में बांट ली जाती थी। सारनाथ एसीपी विदुष सक्सेना ने बताया कि यह एक गिरोह है, जो ऑनलाइन गेमिंग की लत का फायदा उठाकर अपराध कर रहा था। ठगी और लूट के जरिए हासिल रकम गेमिंग खातों में भेजी जाती थी, जहां से कमीशन काटने के बाद पैसे वापस मिल जाते थे।

प्रेम विवाह का विरोध करने पर सब्जी विक्रेता पर चापड़ से हत्या

प्रयागराज, (संवाददाता)। घूरपुर थाना क्षेत्र के डेरा चकिया गांव में सोमवार तड़के 55 वर्षीय किसान तिलकधारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजन ने गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि हाल में किसान के बेटे ने गांव की लड़की के साथ कोर्ट मैरिज की थी। लड़की के परिवार से विवाद चल रहा था, जो घटना की वजह हो सकता है। आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घूरपुर थाना क्षेत्र के डेरा चकिया निवासी तिलकधारी गांव में खेती कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी, पांच बेटियां और दो बेटे हैं। पुलिस के अनुसार, 20 मई को गांव निवासी गंगा प्रसाद की बेटी सुहानी, तिलकधारी के भाई अर्जुन के बेटे शिवम के साथ चली गई थी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।